www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 98 | जौनपुर, बुधवार, 25 नवम्बर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अदालत ने दोनों आरोपियों की अंतरिम जमानत की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत पर कोई फैसला लेने से पहले दिल्ली पुलिस का पक्ष सुना जाएगा।बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत की मांग पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाना जरूरी है। इसके बाद ही अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार किया जाएगा। इस फैसले के बाद उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अदालत की ओर से जारी नोटिस के जरिए दिल्ली पुलिस से इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। यह मामला वर्ष 2020 में उत्तर–पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित बड़ी साजिश से संबंधित है। इस मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश थी। आरोपी इन आरोपों के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब दिल्ली पुलिस के जवाब और अगली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।

संविधान दिवस पर देशभर में कांग्रेस निकालेगी संविधान रक्षा मार्च

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर देशभर में श्संविधान रक्षा मार्चश आयोजित करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाले मार्च में शामिल होंगे। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को लेकर सभी राज्यों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस समितियों की अगुवाई में अलग–अलग स्थानों पर मार्च निकाले जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और संवैधानिक मूल्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेगी।कांग्रेस के कार्यक्रमों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ भी किया जाएगा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने की अपील की गई है। लखनऊ में खरगे की मौजूदगी को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।एक तरफ कांग्रेस संविधान दिवस पर देशव्यापी कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन विवादों में घिरता दिखाई दे रहा है।

राधे-राधे तो शुरुआत है, विपक्षी के लिए अब राम नाम सत्य का समय, गठबंधन पर योगी का तीखा हमला

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर एक साथ तीखा हमला बोलते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमा दिया है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि दो नावों की सवारी करने वाले डूबते हैं। अखिलेश को अयोध्या जाने से पहले रामभक्तों और हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि राधे–राधे तो शुरुआत है, सपा के लिए अब राम नाम सत्य का समय आ रहा है। मथुरा में राधे–राधे, अयोध्या में जय श्रीराम और काशी में हर–हर महादेव कहना आस्था के अनुरूप है, जबकि राम नाम सत्य विदाई के समय कहा



जाता है। मुख्यमंत्री बुधवार को एक टीवी मीडिया समूह को दिए साक्षात्कार में बोल रहे थे। योगी ने सपा की राजनीति को परिवार तक सीमित बताते हुए उसके पीडीए की नई व्याख्या की। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सपा की राजनीति परिवार के इर्द–गिर्द घूमती है, जबकि भाजपा का मतदाता हर वह राष्ट्रवादी नागरिक है, जो संविधान और देश की विरासत का सम्मान करता है। उनकी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन देश और समाज के सामने चुनौती आने पर उसका सामना करना संन्यासी का दायित्व है। सपा–कांग्रेस में तालमेल नहीं, चुनाव से पहले ही गठबंधन विफल मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने इसे चुनाव से पहले ही विफल करार देते हुए कहा कि एक तरफ दोनों दलों की बैठकें चल रही हैं और दूसरी तरफ प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। दोनों दलों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने प्याज भी खाया और जूता भी। योगी ने स्पष्ट किया कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों का चयन पार्टी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया।

पिछली सरकारों में दंगों और तुष्टीकरण ने छीनीं हजारों परिवारों की खुशियां – ब्रजेश पाठक

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पिछली सरकारों पर सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्था और परंपराओं की अनदेखी करने तथा तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में दंगों और सांप्रदायिक हिंसा ने हजारों परिवारों की खुशियां छीन लीं। लोगों को अपना घर–बार छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और कई परिवारों ने अपनों को खोया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं में प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय कई बार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप लगे। ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में सनातन संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी धार्मिक परंपराओं को अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, दंगों और सांप्रदायिक हिंसा ने हजारों परिवारों की खुशियां छीन लीं। लोगों को अपना घर–बार छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कितने ही परिवारों ने अपनों को खोया और कितने बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी रहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय कई बार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप लगे। उप मुख्यमंत्री ने बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लव जिहाद के नाम पर सामने आए अनेक मामलों ने समाज को चिंतित किया है। भोली–भाली बेटियों को बहला–फुसलाकर उनकी पहचान छिपाने, धोखे से संबंध बनाने और विवाह के बाद उन्हें प्रताड़ित करने तक की घटनाएं सामने आई हैं।



एआई के दौर में युवाओं को कौशल से लैस करने पर जोर, पीएम मोदी ने साझा किया केंद्रीय मंत्री का लेख

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी का एक लेख साझा किया है। इसमें देश में कौशल विकास पर बढ़ते जोर और कौशल प्रशिक्षण को युवाओं के लिए करियर के पसंदीदा विकल्प के रूप में स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया गया है। लेख में बताया गया है कि सरकार की विभिन्न पहल युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में उभर रहे नए



अवसरों के लिए तैयार कर रही हैं। जयंत चौधरी ने अपने लेख में आगामी 'विश्व कौशल एशिया 2027', औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उन्नत करने की 'पीएम–सेतु' पहल और उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण को मजबूत करने के प्रयासों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि इन पहलों के माध्यम से युवाओं को बदलती तकनीक और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करने पर ध्यान दिया जा रहा है। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के बीच युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना जरूरी है। कौशल प्रशिक्षण को करियर के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में स्थापित करने से युवाओं के लिए रोजगार और नए अवसरों के रास्ते खुल सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "भारत अपनी कौशल विकास यात्रा को वैश्विक मंच पर ले जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कौशल विकास पर देश के बढ़ते ध्यान और कौशल प्रशिक्षण को करियर के पसंदीदा विकल्प के रूप में अपनाने के महत्व के बारे में लिखा है।

जनसमस्याओं के समाधान पर फोकस, मुख्यमंत्री करेंगे सीधे संवाद

गांधीनगर, (एजेंसी)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुरुवार, 26 नवंबर को मासिक राज्य स्तरीय श्स्वागतश कार्यक्रम के तहत जनता की शिकायतें सुनेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना और शासन–प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। शिकायतों की प्रकृति के आधार पर संबंधित विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाएंगे।गुजरात सरकार का श्स्वागतश कार्यक्रम जनशिकायतों के निवारण की दिशा में एक



महत्वपूर्ण पहल है। इसका आयोजन सामान्यतः प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को किया जाता है। इस कार्यक्रम में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनका समाधान स्थानीय प्रशासन के स्तर पर नहीं हो पाया है। तकनीक के इस्तेमाल से शिकायतों की सुनवाई और उनके निराकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया गया है।राज्य स्तरीय स्वागत कार्यक्रम के जरिए विभिन्न जिलों से आने वाले नागरिक अपनी समस्याओं और लंबित मामलों को मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों से शिकायतों के संबंध में जानकारी ली जाती है। आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों और प्रशासनिक पक्ष की समीक्षा के बाद नियमानुसार समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।श्स्वागतश का पूरा नाम स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेज बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी (ळ।ज) है। गुजरात में इस पहल की शुरुआत वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई थी। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य तकनीक के माध्यम से जनता और सरकार के बीच की दूरी कम करना तथा नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना था।इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को प्रशासनिक स्तर पर लंबित शिकायतों के संबंध में उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिलता है।

मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे- मोहन यादव

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी के लिए खुशखबरी आई है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह ऐलान किया है कि आउटसोर्स कर्मचारी को बाहर नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास (संवाद भवन) में बुधवार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर करने के संबंध में फैलाई जा रही बात भ्रामक है, राज्य सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को बाहर नहीं किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में वर्तमान में जारी व्यवस्था कायम रहेगी।सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसी सरकार की



ताकत और पहचान कर्मचारियों की बुलंदी से होती है। कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान होगी, तभी प्रदेश प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राज्य सरकार और अधिकारी–कर्मचारी एक परिवार की तरह कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग के अध्यक्ष रमेश शर्मा के नेतृत्व में लगभग 40 कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का गजमाला से भव्य स्वागत किया। साथ ही शासकीय सेवाओं में नियुक्ति और कार्यरत कर्मचारियों के लिए दो संतान की सीमा की नीति को अनिवार्यतरू समाप्त करने, पदोन्नति, वेतन भत्तों में वृद्धि सहित अनेक कल्याणकारी निर्णयों के लिए कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री यादव का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार नीतियां बनाती है, योजनाएं तैयार करती है, लेकिन उन्हें लागू कर अंतिम पंक्ति के जरूरतमंद को लाभ हमारे कर्मचारी ही दिलवाते हैं। कर्मचारियों का सम्मान और उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कर्मचारियों के प्रति संवेदनाएं रखनी चाहिए। कई काम ऐसे होते हैं, जिन्हें करने में आत्मीय सुख होता है, जिसका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए निर्णय भी इसी प्रकार के कार्य हैं। राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए दो बच्चे की सीमा की नीति को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

कैबिनेट ने 'पोस्टल ऑपरेशंस' योजना के लिए मंजूर किए 1,141 करोड़ रुपये

मुंबई, (एजेंसी)। देश के सबसे बड़े डाक नेटवर्क 'इंडिया पोस्ट' को आधुनिक और हाई–टेक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग चक्र (वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2030–31) के लिए 1,141 करोड़ रुपये के बजट के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'पोस्टल ऑपरेशंस' (डाक संचालन) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पांच साल तक चलने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य डाक बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, अंतिम छोर तक डिलीवरी (लास्ट–माइल डिलीवरी) को मजबूत बनाना और ई–कॉमर्स लॉजिस्टिक्स व डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। वर्तमान में इंडिया पोस्ट के पास देशभर में 1.65 लाख डाकघर हैं, जिनमें से 1,49,655 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। दूर–दराज के इलाकों में यह नेटवर्क डाक और



पार्सल के अलावा कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। इनमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आधार नामांकन और अपडेट, पासपोर्ट सेवा केंद्र, केवाईसीसत्यापन और 'डाकघर निर्यात केंद्रों'के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों को निर्यात सहायता शामिल है। यह नई योजना 'डिजिटल इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' के लक्ष्यों को गति देगी। मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन (575 करोड़ रुपये) सबसे बड़ा हिस्सा मेल संचालन के आधुनिकीकरण पर खर्च होगा।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश रद्द

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को



शिकायत में लगाए गए आरोपों का सत्यापन करने और मामले में हुई प्रगति की जानकारी हाईकोर्ट को देने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को राहुल गांधी के लिए कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास वापस भेज दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि राहुल गांधी को मामले में पक्षकार बनाया जाए और कोई आदेश पारित करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। अदालत के इस फैसले के बाद हाईकोर्ट में मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी। दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को आरोपों का सत्यापन करने और संबंधित कार्रवाई की प्रगति से अदालत को अवगत कराने के निर्देश दिए थे।राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में उन्होंने हाईकोर्ट की ओर से अपनाई गई न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

15 दिन में एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं से गुलजार हुई रामनगरी, कारोबार को भी मिली नई रफ्तार

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। कार्तिक माह में रामनगरी अयोध्या श्रद्धा, भक्ति और पर्यटन के नए रिकॉर्ड के साथ गुलजार रही। दीपोत्सव से लेकर चौदह कोसी–पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान तक बीते 15 दिनों में एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने सूर्यकुंड, गुप्तारघाट और भरतकुंड जैसे धार्मिक स्थलों का भी रुख किया। श्रद्धालुओं की भारी आमद से जहां रामनगरी भक्तिमय रही, वहीं स्थानीय व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन और दुकानदारों को भी बड़ी आर्थिक राहत मिली।सरकारी आंकड़ों के अनुसार दीपोत्सव में करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे,जबकि चौदह कोसी परिक्रमा में लगभग 30 लाख और पंचकोसी परिक्रमा में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान पर्व पर भी लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। इन धार्मिक आयोजनों के दौरान रामनगरी के प्रमुख मंदिरों, घाटों और पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी रही। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में धार्मिक पर्यटन का विस्तार तेजी से हुआ है। योगी सरकार की ओर से सड़क, रेलवे, हवाई सुविधा, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ–सफाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से श्रद्धालुओं को आवागमन और दर्शन में सहूलियत मिली।धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन की तैयारियां भी अहम रहीं।श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का असर स्थानीय कारोबार पर भी दिखाई दिया। हनुमानगढ़ी और रामकोट क्षेत्र के दुकानदारों के मुताबिक दीपोत्सव से कार्तिक पूर्णिमा तक बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फूल–माला, प्रसाद,



पूजा सामग्री, स्मृति चिह्न, होटल और खानपान से जुड़े कारोबारियों ने भी अच्छी आमदनी होने की बात कही। व्यापारियों का कहना है कि जिस कारोबार को पहले पूरे वर्ष में हासिल करना मुश्किल होता था, वह इन 15 दिनों में हो गया। स्थानीय कारोबारियों ने अयोध्या में जारी विकास कार्यों और बेहतर सुविधाओं को पर्यटन वृद्धि का प्रमुख कारण बताया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि दीपोत्सव, परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पेयजल, शौचालय, चिकित्सा, सुरक्षा और यातायात सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को विभागीय समन्वय से सुनिश्चित किया गया, जिससे धार्मिक आयोजन सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

संपादकीय

जड़ कमजोर करते हुए

राजकोष गहरे दबाव में है। लेकिन सियासी पार्टियों के लिए चुनावी राजनीति के नए उभरते तकाजे कहीं ज्यादा अहम हैं। इसलिए वे अपने वर्तमान को सुरक्षित रखने के लिए देश के भविष्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह ऐसी चेतावनी है, जिन पर ना सिर्फ ध्यान दिया जाना चाहिए, बल्कि जिस पर अब गंभीर राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। चेतावनी इस हकीकत पर आधारित है कि राज्य सरकारों के पास सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपेक्षाकृत कम बच रहा है। इसलिए कि सरकारी खजाने का ज्यादातर पैसा रोजमर्रा के खर्च, वेतन, पेंशन, और सब्सिडी में चला जाता है। अब ऊपर से ष्वोट खरीदनेष का बढ़ा चलन है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने अपनी ताजा स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंसेज रिपोर्ट में इस पर जोर देना जरूरी समझा है कि 2027 में जिन सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां बिना शर्त नकद हस्तांतरण योजनाएं फिर चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनती दिख रही हैं। रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है कि इन सात राज्यों ने 2026–27 के लिए कुल मिलाकर 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ऐसी योजनाओं के लिए बजट में रखी है। वैसे देश के सभी राज्यों को मिला लिया जाए, तो यह आंकड़ा करीब चार लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। गौर कीजिए 2022–23 में यह राशि करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये थी यानी सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत के करीब। 2026–27 में इसके बढ़कर जीडीपी के करीब एक प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। इसके ऊपर सब्सिडी पर होने वाला खर्च है। पीआरएस के मुताबिक 2024–25 में 29 राज्यों ने सब्सिडी पर 4.4 लाख करोड़ रुपये खर्च किए, जो उनकी कुल राजस्व प्राप्तियों का 11 प्रतिशत था। जाहिर है, राज्यों का बजट गहरे दबाव में है। लेकिन सत्ताधारी दलों और नेताओं के लिए चुनावी राजनीति के नए उभरते तकाजे कहीं ज्यादा अहम हैं। इसलिए वे अपने वर्तमान को सुरक्षित रखने के लिए देश के भविष्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस रुझान पर सर्वदलीय सहमति है। पीआरएस ने उचित ही ध्यान दिलाया है कि जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, उनमें पांच में भाजपा की सरकार है। एक में कांग्रेस और एक में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और वे सभी श्वोट खरीद्य योजना में समान रूप से तल्लीन हैं।

संतुलित विकास की सोच से ही बच सकती है दुनिया



उमेश

देश अभी सूखे के दुष्प्रभाव से निबटने की कोशिश कर ही रहा था कि महज एक हफ्ते के भीतर बंगाल की खाड़ी से उठे दो–दो तूफानों ने इसके तटीय इलाकों में कहर बरपा गया। तकनीकी विकास की वजह से तूफानों की पूर्व सूचना के चलते सरकारों ने एहतियाती उपाय कर लिए, इस वजह से बहुत ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तटीय इलाकों के बुनियादी ढांचे, बिजली व्यवस्था आदि को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचाने में सफल रहा। अर्नब जहां 28–29 अक्टूबर को आया तो दो नवंबर को मुरासू कहर बनकर उभरा। इतिहास में कम ही मौके ऐसे आए होंगे, जब सिर्फ एक हफ्ते के भीतर दो–दो तूफान आए। इन दोनो तूफानों ने ना सिर्फ माली नुकसान पहुंचाया, बल्कि मौसम चक्र को भी बदलकर रख दिया। दोनों के असर से उत्तर भारत तक के मौसम में बदलाव दिखने लगा है। करीब डेढ़ दशक से उत्तर भारत में देर से दस्तक देने वाला ठंड का मौसम कुछ पहले ही आ गया है। विगत कुछ दशकों से भारत ही नहीं दुनिया के मौसम चक्र में बदलाव दिख रहा है। इसकी वजह से वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, बारिश का चक्र या तो कमजोर पड़ रहा है या फिर अचानक ही किसी इलाके में तीव्र हो जा रहा है। इसके चलते जहां वनस्पतियों की जहां कुछ प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, वहीं जंतु जगत के कार्यकलाप, आदत और अस्तित्व में परिवर्तन नजर आने लगे हैं। इसका असल फसल चक्र और उनकी पैदावार पर भी पड़ रहा है। अव्वल तो दुनिया को इन बदलावों से चिंतित होना चाहिए, विश्व परेशान भी दिखता है, लेकिन इस बदलाव को थामने की वैश्विक स्तर पर जैसी संजीदा कोशिश होनी चाहिए, नहीं हो रही है।इसे भी पढ़ेंरू दाल–तेल–दूध–चीनी सब महंगा हो रहा...क्या सच में आर्थिक आपदा की कगार पर भारत? विदेशी धरती से राहुल ने अब फोड़ा कौन सा नया बम! मोटे तौर पर इस बदलाव के पीछे मनुष्य का लालच और समृद्धि हासिल करने की उसकी चाहत काम कर रही है। उन्नीसवीं सदी की औद्योगिक क्रांति के पहले तक पूरी दुनिया में संतुलित उपभोग का सिद्धांत काम करता था। औद्योगीकरण के बढ़ते कदम के साथ इस सोच में कमी आई। लेकिन उदारीकरण के तेज बढ़ते कदमों की वजह से दुनिया में उपभोगवाद को बढ़ावा। जैसे–जैसे उपभोग की संस्कृति बढ़ती गई, उत्पादन की मांग बढ़ती गई। उत्पादन के चलते प्रकृति का दोहन बढ़ा, ऊर्जा की मांग बढ़ी। इस पूरी प्रक्रिया में प्रकृति और सभ्यता के बीच संतुलन गड़बड़ाना शुरू हुआ। जिसका असर जलवायु परिवर्तन के रूप में दिख रहा है। महात्मा गांधी बहुत पहले इस व्यवस्था को लेकर दुनिया को चेता चुके थे। उपभोगवाद को नियंत्रित रखने की कल्पना उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका हिंद स्वराज में की है। 1909 में लिखी इस पुस्तिका में गांधी ने लिखा है, "हम देखते हैं कि मन एक बेचौन पक्षी हैय जितना अधिक इसे मिलता है, उतना ही यह चाहता है और असंतुष्ट रहता है। हम जितना अधिक अपने जुनून में लिप्त होते हैं, वे उतने ही बेलगाम होते जाते हैं। इसलिए, हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से दूर रखा।" आज दुनिया ने शहरीकरण और औद्योगीकरण को विकास का पैमाना मान लिया है। दोनों ने ही हमारे जीवन में उपभोगवाद को बढ़ावा दिया है। इसकी वजह से हमारी जलवायु में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। इसका सबसे स्पष्ट संकेत यह है कि दुनिया गर्म हो रही है। वैज्ञानिकों को यह बात उपग्रहों, मौसम संबंधी गुब्बारों, थर्मामीटरों, मौसम केंद्रों और अन्य स्रोतों से जुटाए गए सबूतों से पता चली है। 1880 के बाद से, विश्व के औसत तापमान में लगभग एक डिग्री सेल्सियस यानी करीब 1.7 डिग्री फारेनहाइट की वृद्धि हुई है। अगर शहरीकरण और औद्योगीकरण केंद्रित उपभोगवाद यूं ही जारी रहा तो अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी करीब 2.7 डिग्री फारेनहाइट और साल 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, 1960 के दशक से वैश्विक औसत वार्षिक तापमान में लगातार वृद्धि हुई है। इसके आंकड़ों के अनुसार, 20वीं सदी के बाद से सबसे गर्म रहे 20 वर्षों में से 19 वर्ष सिर्फ 2001 के बाद के हैं। आशंका है कि भविष्य में आने वाला सबसे ठंडा वर्ष भी, 20वीं सदी के सबसे गर्म वर्ष की तुलना में अधिक गर्म होगा। विस्कॉन्सिन में तापमान और वर्षा में आए बदलावों का पता लगाने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन–मैडिसन के वैज्ञानिकों ने श्नेशनल क्लाइमेटिक डेटा सेंटरश द्वारा पूरे राज्य के नेटवर्क से जुटाए गए तापमान रिकॉर्ड का विश्लेषण किया है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि 1950 के दशक के बाद से विस्कॉन्सिन का तापमान 2 डिग्री फारेनहाइट बढ़ गया है, साथ ही यहाँ बारिश में 4.5 इंच यानी करीब 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा तापमान सर्दियों में बढ़ा है, जबकि वर्षा में सबसे अधिक वृद्धि गर्मियों के दौरान हुई है। स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के डॉ. चार्ल्स डेविड कीलिंग द्वारा शुरू की गई वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की दैनिक रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड में घटत–बढ़त होती रही है। जाहिर है कि इसका असर भी मौसम चक्र पर पड़ रहा है। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा है। वसंत के मौसम में जब पौधे बढ़ते हैं, तो वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके उसे कार्बन में बदल देते हैं, साथ ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वहीं, पतझड़ के मौसम में जब पौधे नष्ट होते हैं, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर इसकी मात्रा में बढ़त दिखती है। मौसमी बदलावों के अलावा कीलिंग के अध्ययन रिपोर्ट से पता चलता है कि समय के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। उनके अध्ययन के अनुसार, 1958 में जहां इसकी उपस्थिति 313 पार्ट्स प्रति मिलियन थी, वहीं 30 मार्च 2020 तक बढ़कर यह 415 प्रति मिलियन हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में हुई इस वृद्धि को श्कीलिंग कर्वश कहा जाता है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि साल 1900 तक, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जहां स्थिर और लगभग 150 से 280 प्रति मिलियन के बीच था, वहीं 1900 के दशक की शुरुआत में, ब्व्2 का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आज, यानी 120 साल बाद, इसका स्तर औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। साफ है कि जब तक दुनिया इसके प्रति नहीं चेतेगी, मौसम में बदलाव का चक्र नहीं रूकेगा। इससे सभ्यता का भविष्य भी खतरे में होगा।

भारत नया गेम खेल रहा है

हरिशंकर व्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जुमले पर गौर करें– इंडिया इज प्लेइंग अ होल न्यू गेमश्। उन्होने दुनिया में एक बेहद एक पॉपुलर ऑनलाइन गेम जीटीए यानी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम्स के फॉन्ट और उसके ग्राफिक्स के साथ यह बात कही। इसे उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। मतलब एक गेम जीटीए के पांचवें संस्करण से छठे संस्करण की 13 साल की यात्रा की तुलना अपने साढ़े 12 साल के कार्यकाल से की है। उन्होंने युवाओं को समझाया कि जीटीए का एक संस्करण आने में जितना समय लगा उतने समय में उन्होंने भारत को बदल दिया। यह बताने के लिए मोदी ने आर्थिक विकास के 2014 और 2026 के आंकड़ों की तुलना की। उन्होंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल फाइव से निकल कर दुनिया की सबसे तेज बढ़ती पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अत्यधिक गरीबों की आबादी 27 से घट कर 2.6 फीसदी रह गई है। 20 फीसदी से बढ़ कर विद्युतीकरण 99 फीसदीसे ज्यादा हो गया है। सौ फीसदी स्वच्छता कवरेज है। सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 से बढ़ कर 175 गीगाबाइट हो गई है और इंटरनेट डेटा की कीमत 308 रुपए प्रति जीबी से घट कर साढ़े सात रुपए प्रति जीबी हो गई है। उन्होंने कहा कि 440 स्पेस स्टार्टअप हो गए हैं और 80 से ज्यादा देशों को भारत रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। निश्चित रूप से मोदी जीटीए के डेवलपमेंट को फॉलो नहीं करते होंगे। वे यह नहीं जानते यह गेम एक श्अपराधी जोड़ीश्च या श्क्रिमिनल ड्यूओश्च की कहानी है, जिसकी ओर कांग्रेस के जयराम रमेश ने इशारा किया। लेकिन उनकी टीम ने बताया होगा कि यह नई परिघटना है और लॉन्च होते ही जीटीए–6 के लाखों यूजर्स बन गए हैं। ध्यान रहे यह कंपनी स्कॉटलैंड की है। वहां के आईटी के पेशेवरों ने इसे बनाया है। अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप और भारत में भी बड़े चाव से यह गेम खेला जाता है। जाहिर है बड़ा स्टार्टअप है यह, जिसकी चर्चा भारत के प्रधानमंत्री ने भी की। सवाल है क्या भारत का कोई स्टार्टअप है, जिसकी ऐसी ही चर्चा दुनिया के किसी और देश में हो? पर भारत की उपलब्धि क्या है? भारत विदेशी ऑनलाइन गेम्स खेलने में रिकॉर्ड बना रहा है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में हैं। ऐसे ही एआई के भी सर्वाधिक यूजर भारत में हैं। अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन का भी सर्वाधिक इस्तेमाल भारतीय करते हैं। लेकिन इनमें से भारत का अपना क्या है? क्या भारत ने कोई ऑनलाइन गेम बनाया है या कोई प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में किया जा रहा हो। चीन का टिकटॉक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। अमेरिका का यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स आदि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्कॉटलैंड में बना जीटीए पूरी दुनिया खेलती है। लेकिन भारत का क्या? डेटा सस्ता होने से भारत के लोग इन सब प्लेटफॉर्म के यूजर बने हैं। जब प्रधानमंत्री इन प्लेटफॉर्म्स का हवाला देकर भारत के विकास का दावा करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि तकनीक की दुनिया में भारत की खुद की क्या उपलब्धि है? प्रधानमंत्री ने जितनी उपलब्धियों का जिक्र किया है वह सब जेनेरिक हैं। कुछ भी नया नहीं है। पहले 39 फीसदी स्वच्छता कवरेज था और अब एक सौ फीसदी हो गया है, इस दावे का कोई अर्थ नहीं है। भारत अब भी दुनिया का सबसे गंदा और सबसे प्रदूषित हवा, पानी वाला देश है। ऐसे ही सौर ऊर्जा पहले कम बनती थी और अब बहुत बनने लगी है यह जेनेरिक विकास है। जैसे जैसे नई तकनीक आ रही है वैसे वैसे ऊर्जा उत्पादित करने की क्षमता बढ़ रही है। हकीकत यह है कि सौर ऊर्जा के लिए जरूरी तकनीक, सोलर प्लेट्स आदि चीन से ही आता है। पहले इतनी सड़क बनती थी अब इतनी बनती है या पहले इतनी रेल लाइन बिछती थी और अब इतनी बिछती है यह जेनेरिक विकास के आंकड़े हैं। कांग्रेस चाहे तो बता सकती है कि उसके पहले की सरकारों में कितने फोन थे और उसके समय कितने हुआ या उससे पहले कितनी सड़कें बनती थीं और उसके समय में कितनी बनीं। इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता है। असली बात यह है कि नया क्या आविष्कार हुआ? भारत ने ऐसा क्या बनाया कि पूरी दुनिया ने हैरान रह गई और पूरी दुनिया में उसे हाथों हाथ लिया गया। दुनिया ने कुछ बनाया और अपनी आबादी की वजह से हम सबसे बड़े यूजर बन गए यह कोई उपलब्धि नहीं है। भारत ने सर्वमएआई को संप्रभु प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित करने के लिए चुना था। इसे करीब एक करोड़ रुपए के चिप्स उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें एनवीडिया के भी चिप्स थे। अब खबर है कि भारत के कथित संप्रभु सर्वमएआई भारत के चिप्स यानी जीपीयू पर चीन के एआई मॉडल्स को होस्ट कर रहा है और बेच रहा है। इसी हफ्ते सर्वमएआई ने श्टोकन फैक्टरीश्च नाम से अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिस पर वह स्वदेशी मॉडल के साथ साथ चीन के डीपसीक, किमी और जीएलएम जैसे मॉडल्स को भी होस्ट कर रहा है और बेच रहा है।

जनता ने नकार दिया भजनलाल शर्मा का नेतृत्व

नीरज

राजस्थान की राजनीति में गांवों की चौपाल से उठने वाला संदेश अक्सर सत्ता के गलियारों तक पहुंचते–पहुंचते बड़ा सियासी सवाल बन जाता है। पंचायत चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर सामने आई तस्वीर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व, सरकार की कार्यशैली और प्रदेश भाजपा संगठन के भीतर तालमेल को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर भाजपा ने जिस राजनीतिक उम्मीद के साथ भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी, उस उम्मीद के बाद अब तक हुए चुनावी पड़ावों को लेकर पार्टी के सामने आत्ममंथन की स्थिति बनी हुई है। सवाल केवल पंचायत चुनावों में हार–जीत का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक दिशा का है जिसके सहारे भाजपा राजस्थान में अपना जनाधार मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। देखा जाये तो राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री का पद केवल प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नहीं होता, बल्कि पार्टी के अलग–अलग धड़ों, क्षेत्रीय क्षत्रपों, संगठन और जनता के बीच राजनीतिक संतुलन कायम रखने की भी जिम्मेदारी होती है। भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में इन सभी मोर्चों पर समन्वय को लेकर समय–समय पर सवाल उठते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी थी, लेकिन उसे 14 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 11 सीटें हासिल कर भाजपा के उस राजनीतिक दबदबे को चुनौती दी, जिसे पार्टी विधानसभा चुनावों की जीत के बाद अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही थी। इसके बाद इस साल सितंबर में हुए शहरी निकाय चुनावों की तस्वीर भी भाजपा के लिए पूरी तरह एकतरफा नहीं रही। प्रदेश के 7,475 शहरी वार्डों में भाजपा को 3,054 और कांग्रेस को 2,786 सीटें मिलीं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 1,635 वार्डों में जीत दर्ज की। दस नगर निगमों में भाजपा पांच में आगे रही, कांग्रेस तीन में और एक में निर्दलीय आगे रहे, जबकि जोधपुर में मुकाबला बराबरी का रहा। यानी शहरी निकायों में भी भाजपा को ऐसा निर्विवाद जनसमर्थन नहीं मिला, जिसकी उम्मीद सत्ता में बैठी पार्टी कर सकती थी। अब पंचायत चुनावों ने इस राजनीतिक तस्वीर को और स्पष्ट कर दिया है। गांवों में भाजपा को जिस तरह कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों से चुनौती मिली, उसने प्रदेश सरकार के लिए नई राजनीतिक परिस्थिति पैदा कर दी है। देखा जाये तो राजस्थान के 37 जिलों में आए पंचायत चुनाव परिणाम भाजपा के लिए खासे महत्वपूर्ण हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति के नतीजों में कांग्रेस ने भाजपा से कहीं अधिक सीटें हासिल कीं। पंचायत समिति के 7,543 वार्डों में कांग्रेस ने 3,758 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा 2,213 सीटों पर सिमट गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 497 और भारत आदिवासी पार्टी को 278 सीटें मिलीं। जिला परिषद की 1,275 सीटों में भी कांग्रेस ने 794 और भाजपा ने 357 सीटें हासिल कीं। 37 जिलों में से 23 में कांग्रेस को बहुमत मिला, जबकि भाजपा पांच जिलों में बहुमत हासिल कर सकी। आठ जिलों में निर्दलीय निर्णायक स्थिति में रहे। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा की चुनौती केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं रही। पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और आदिवासी क्षेत्रों में बीएपी की मौजूदगी ने यह दिखाया कि ग्रामीण राजनीति में स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय मुद्दों की अपनी ताकत है। वैसे भी पंचायत चुनावों में मतदाता केवल जयपुर या दिल्ली के राजनीतिक नारों पर नहीं, बल्कि अपने इलाके के प्रतिनिधियों और स्थानीय समस्याओं पर भी फैसला करते हैं। के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में एक नया राजनीतिक प्रयोग किया था। पार्टी ने अनुभवी और स्थापित चेहरों के बजाय पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को प्रदेश की कमान सौंपी थी। यह फैसला पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व का था और इसके पीछे संगठनात्मक तथा राजनीतिक रणनीति काम कर रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को साधने की थी। राजस्थान में भाजपा की राजनीति लंबे समय से वसुंधरा राजे के इर्द–गिर्द ही घूमती रही है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के लिए पुराने और वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी था। यहीं से सरकार और संगठन के भीतर समन्वय को लेकर सवाल उठने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अप्रैल 2025 में झालावाड़ में पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी। उनका सवाल था कि जब जनता पानी के लिए परेशान है तो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं?



यह केवल अधिकारियों के कामकाज पर नाराजगी नहीं थी, बल्कि सरकार के सामने खड़ी स्थानीय समस्याओं की गंभीरता को भी उजागर करता था। देखा जाये तो राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का अपना जनाधार और राजनीतिक प्रभाव रहा है। ऐसे में उनकी सार्वजनिक नाराजगी को महज एक प्रशासनिक टिप्पणी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह घटनाक्रम इस सवाल को भी जन्म देता है कि क्या मुख्यमंत्री प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और सरकार के बीच ऐसा संवाद स्थापित कर पाए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर उठने वाली समस्याओं का समय रहते समाधान हो सके। इसके अलावा, भजनलाल सरकार के शुरुआती कार्यकाल में ही कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बना था। लोकसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। करीब दस महीने तक उन्होंने नियमित मंत्री की तरह कामकाज से दूरी बनाए रखी थी। इस दौरान उनके इस्तीफे की स्थिति, मंत्रिमंडल की बैठकों से उनकी अनुपस्थिति और विभागीय कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। अप्रैल 2025 में केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने दोबारा मंत्री के रूप में कामकाज संभाला था। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था ।

वाटरलू संवाद में छिपा अर्थव्यवस्था का बड़ा राज



अभिनय

सरकार ने टैक्स घटाया और कारोबार को आसान बनाया, लेकिन कंपनियों ने उसका फायदा जो है अपने यहां काम कर रहे वर्कर्स तक नहीं पहुंचाया, उनको बेनिफिट नहीं दिया। 19 नवंबर का दिन था जब प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत पर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज पर तीखा हमला बोला। देश के शीर्ष उद्योगपतियों के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में जो तल्खी, हताशा और एक तरह की बेबसी झलक रही थी, उसने आर्थिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उनका अंदाज कुछ ऐसा था मानो वे कॉर्पोरेट जगत से सीधे पूछ रहे हों कि आखिर आपको आगे बढ़ने और निवेश करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? यह महज दिल की पुकार से कहीं अधिक गंभीर बात थी। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कोई सेनापति अपने सैनिकों से मोर्चे पर आगे बढ़कर पहाड़ी पर चढ़ाई करने का आह्वान करे, लेकिन सैनिक अपनी जगह से टस से मस न हों, चाहे सेनापति उन्हें कितना ही क्यों न ललकारे। इस स्थिति को समझने के लिए 1970 की मशहूर फिल्म वाटरलू का एक संवाद बेहद सटीक बैठता है। फिल्म में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का किरदार निभा रहे क्रिस्टोफर प्लमर, डचेस ऑफ रिचमंड से कहते हैं, कौन जानना चाहेगा कि सैनिकों को लड़ने का जोश कहाँ से मिलता है? जिन (शराब) ही उनके देशभक्ति के जुनून का असली स्रोत है। बेशक, प्रधानमंत्री का इरादा कॉर्पोरेट इंडिया को उन कठोर शब्दों से नवाजने का कतई नहीं था जो वेलिंगटन ने अपने सैनिकों के लिए इस्तेमाल किए थे, लेकिन उनकी हताशा की गहराई कुछ वैसी ही महसूस हो रही है। सवाल यह है कि कोई सरकार उद्योगपतियों को आगे बढ़ने के लिए किस तरह का जोश या टॉनिक दे सकती है? इसका जवाब है उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसमें नियमों में ढील, मिनिमम गवर्नमेंट, बाजार की निष्पक्ष निगरानी, वित्तीय अनुशासन और लाइसेंसिंग व निवेश की पाबंदियों से आजादी जैसे कदम शामिल हैं। यदि हम वेलिंगटन वाले जिन के उदाहरण को यहाँ लागू करें, तो इस प्रोत्साहन पैकेज का सबसे बड़ा और असरदार हिस्सा है, टैक्स में भारी कटौती। प्रधानमंत्री की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार द्वारा दी गई इन तमाम रियायतों और बढ़ते कॉर्पोरेट मुनाफे के बावजूद, उद्योग जगत इसका लाभ आम लोगों और अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुँचा रहा है। न तो उस अनुपात में कर्मचारियों का वेतन बढ़ रहा है, न नई भर्तियाँ हो रही हैं, और न ही निजी निवेश में वैसी तेजी दिख रही है। ऐसा लगता है मानो कॉर्पोरेट जगत के ये सैनिक मोर्चे पर जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। या तो वे जोखिम उठाने से डर रहे हैं, या फिर अपने सुरक्षित दायरे में बैठकर टैक्स छूट का मजा लेने में ही उन्हें ज्यादा आराम मिल रहा है। प्रधानमंत्री की यह पीड़ा फिक्की के कार्यक्रम में दिए गए उनके भाषण में साफ सुनाई दी। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हिसाब देते हुए याद दिलाया कि 2014 में देश में मूल कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत हुआ करती थी, जिसे उनकी सरकार ने घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया। इतना ही नहीं, आज भारत में 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों की चुटकी लेते हुए जो तंज कसा, वह उनके मन की पूरी बात कह गया। उन्होंने कहा मुझे पता है कि आप तालियां बजाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को चाहे कितना भी दे दिया जाए, आपकी भूख कभी शांत ही नहीं होती। अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को सीधा आईना दिखाया। उनके सटीक शब्द थे क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या आपने नए लोगों को नौकरी पर रखा? नहीं! आपका रवैया बस यही रहता है कि मोदी जी आप करिए, हम बाद में देखेंगे। यह सीधे तौर पर कॉर्पोरेट इंडिया पर प्रधानमंत्री का एक तीखा तंज था, जिसने उद्योग जगत को सकते में डाल दिया। जहां एक तरफ इंडिया इंक (कॉर्पोरेट जगत) अपने आहत स्वाभिमान को संभालने में जुटा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने तुरंत प्रधानमंत्री के इन शब्दों को लपक लिया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि वे तो शुरू से यही बात कह रहे थे। इस मुद्दे पर सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 12 साल में पहली बार एक घबराए हुए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के दिग्गजों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई है, जिससे वे खुद भी हैरान और स्तब्ध रह गए होंगे। जयराम रमेश ने निवेश में आई इस सुस्ती के लिए कारोबारियों के बजाय सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे क्रोनी कैपिटलिज्म (पूंजीपति मित्रों को बढ़ावा), नियामक संस्थाओं पर कब्जा, डर व धमकी का माहौल और जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल जिम्मेदार है। उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि वे कॉर्पोरेट इंडिया को दोष देने के बजाय खुद के भीतर झांककर देखें। उधर, अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने भी इसी सुर में कहा कि हमने तो पहले ही इस स्थिति को लेकर आगाह किया था। आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत उस रफ्तार से निवेश, विस्तार या नई भर्तियां नहीं कर रहा है, जैसा कि 7 प्रतिशत से अधिक की जीडीपी ग्रोथ के दौर में होना चाहिए। हालांकि देश में स्टार्टअप्स तेजी से उभर रहे हैं, लेकिन पारंपरिक उद्यमिता में एक तरह का ठहराव सा आ गया है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था की ज्यादातर रफ्तार सरकार के अपने खर्च खासकर भारी बुनियादी ढांचे पर किए जा रहे निवेशकृके दम पर टिकी है। यदि आज कॉर्पोरेट इंडिया जोखिम उठाने से इतना कतरा रहा है, तो यह कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि यह मायूसी सालों से अंदर ही अंदर पनप रही थी। एक बेहद शक्तिशाली सरकार होने का मतलब यह नहीं कि नीतियों में भ्रम या बार–बार बदलाव (फिलप–फ्लॉप) नहीं हो सकते। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से हर वित्त मंत्री यही कहता आया है कि एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की पहचान संतुलित और स्थिर टैक्स व्यवस्था होती है। लेकिन मौजूदा दौर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और डिविडेंड टैक्स में जितने बदलाव हुए हैं, उसने निवेशकों के भरोसे को डगमगाया है। इसके अलावा, आज देश में व्यक्तिगत करदाताओं पर कॉर्पोरेट जगत की तुलना में लगभग दोगुना टैक्स लगाया जा रहा है। सरकार ने अपनी संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कई चौंकाने वाले फैसले भी लिए हैं।

संक्षिप्त खबरें

रेशम किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से पहुंचाएं अधिकारी – राकेश सचान

लखनऊ, (संवाददाता)।प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने और रेशम कृषकों की आय में निरंतर वृद्धि करने के लिए सरकार ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन गृह निर्माण और उपकरण वितरण का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराने के बाद ही अगली किस्त की ध नराशि जारी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता या काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।मंत्री ने सोमवार को डालीबाग स्थित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के खादी भवन सभागार में रेशम विभाग की योजनाओं, कृषक प्रशिक्षण और विभागीय प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना, सिल्क समग्र–2 और राज्य कृषि विकास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। मंत्री ने कहा कि रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों को आधुनिक तकनीक और योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026–27 में उत्पादित होने वाली सभी कोया फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 16 जिलों में कोया मंडियों की स्थापना से रेशम कृषकों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। इन जिलों में बहराइच, गोंडा, लखीमपुर, सीतापुर, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, औरैया, मेरठ, सहारनपुर, सोनभद्र, झांसी, फतेहपुर, कानपुर नगर, वाराणसी और पीलीभीत शामिल हैं।

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा तीन दिसंबर को 48 जिलों में होगी

लखनऊ, (संवाददाता)।। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 05ध्2026 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (सम्बद्ध प्राइमरी) और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक (शहरी पद) के लिए लिखित परीक्षा तीन दिसंबर 2026 को प्रदेश के 48 जनपदों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9रू30 से 11रू30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2रू30 से शाम 4रू30 बजे तक निर्धारित की गई है।आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना सोमवार, 23 नवंबर से आयोग की आधि ाकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार, 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवश्यक विवरण दर्ज कर अपने परीक्षा जनपद की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।आयोग ने स्पष्ट किया है कि वेबसाइट पर जारी सूचना केवल परीक्षा जनपद की अग्रिम जानकारी है। इसे प्रवेश पत्र न माना जाए। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 30 नवंबर 2026 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है ।

जुगौली रेलवे क्रॉसिंग पर 24 से 30 नवंबर तक होगा ट्रैक मरम्मत कार्य

लखनऊ, (संवाददाता)। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए गोमतीनगर और बादशाहनगर रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित जुगौली रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इसके चलते 24 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी।रेलवे प्रशासन के अनुसार, गोमतीनगर–बादशाहनगर रेलखंड पर किलोमीटर संख्या 768ध्24–26 के पास समपार संख्या 03 एमएल स्पेशल (जुगौली क्रॉसिंग) पर पीक्यूआरएस मशीन के माध्यम से डाउन लाइन में सीटीआर कार्य प्रस्तावित है। यह क्रॉसिंग राममनोहर लोहिया रोड को फैजाबाद रोड संपर्क मार्ग से जोड़ती है। निर्धारित अवधि ा में मरम्मत कार्य के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को आवागमन में असुविधा हो सकती है।रेलवे प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि इस दौरान निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रेल सुरक्षा और जनहित की दृष्टि से यह कार्य आवश्यक है। असुविधा के लिए प्रशासन ने खेद जताया है।

लखनऊ–मैलानी रेलखंड का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का लिया जायजा''

लखनऊ, (संवाददाता)। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में महिला रेल कर्मचारियों के सम्मान, कल्याण और बेहतर कार्य वातावरण को प्राथमिकता देते हुए मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने सोमवार को मैलानी स्टेशन पर 11 महिला रेलकर्मियों को उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने महिला कर्मचारियों से संवाद कर उनके कार्य अनुभव, कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं और कल्याण से जुड़ी समस्याओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि रेल परिचालन और यात्री सेवाओं में महिला कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उनके लिए सुरक्षित, सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना रेल प्रशासन की प्राथमिकता है।मंडल रेल प्रबंधक ने वरिष्ठ शाखाधिकारियों के साथ लखनऊ जंक्शन से मैलानी जंक्शन तक रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान सिधौली, गोला गोकर्णनाथ और मैलानी रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन भवन, प्लेटफार्म, पैदल उपरिगामी पुल, सिग्नलिंग व्यवस्था, स्टेशन यार्ड और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण का उद्देश्य रेल संचालन की संरक्षा, स्वच्छता, यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता और विकास तथा पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का आकलन करना था।सिधौली स्टेशन पर उन्होंने सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग स्थल, यात्री विश्रामालय और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। गोला गोकर्णनाथ स्टेशन पर प्लेटफार्म, परिसर, खानपान स्टॉल, यात्री प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था और साफ–सफाई की स्थिति देखी। उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा और संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं में लगातार सुधार करने के निर्देश दिए।मैलानी जंक्शन पर मंडल रेल प्रबंधक ने बुकिंग कार्यालय, सर्कुलेटिंग एरिया, एकीकृत क्रू लॉबी, गार्ड रनिंग रूम, प्लेटफार्म, फुट ओवरब्रिज, वाशिंग पिट और सीक लाइन का निरीक्षण किया। इसके अलावा स्टेशन परिसर की स्वच्छता, पेयजल, खानपान स्टॉल, वीआईपी लाउंज तथा पुरुष और महिला प्रतीक्षालयों में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया।

Enthusia 2026 के माध्यम से जीवंत हुआ खेलों का संसार

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल के गोयल स्टेडियम ग्राउंड में २४ नवम्बर २०२६ के दिन विद्यार्थियों ने ष्स्पोर्ट्स म्यूजियमष विषय को जीवंत करते हुए एक आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के माध्यम से खेलों की समृद्ध विरासत और इतिहास को प्रस्तुत किया । स्पोर्ट्स डे का आरंभ गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन महेश अग्रवाल , प्रधानाचार्या डॉ. रीना पाठक, मुख्य अतिथि हिमांशु शेखर झा (प्रोफेसर,पूर्व कुलपति राज्य आयुक्त दिव्यांगजन), विशेष अतिथि तूलिका आनन्द (उप प्रबंधक, सेठ एम. आर .जयपुरिया स्कूल्स), नीलम गोयल (उपाध्यक्ष एवं ट्रस्टी जीआईटी एम), समर्थ गोयल (सी.ई.ओ. गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस)के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं हवा में गुब्बारे छोड़ कर किया गया। जी. जी.आई के सभी विभागों के प्रधानाचार्य एवं लखनऊ के प्रतिष्ठित सीबीएसई विद्यालयों के प्रधानाचार्य भी छात्रों का उत्साहवर्धन करने हेतु उपस्थित रहे।चेयरमैन महेश अग्रवाल ने अपने आशीर्वचनों से छात्रों का उत्साहवध न किया। प्रधानाचार्या ने विद्यालय की उपलब्धियों का ब्यौरा सभी के



साथ साझा किया और कक्षा १० एवं १२ में सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले सभी छात्रों को सम्मानित किया गया।इस आयोजन में विद्यालय के चार समूह गेम चेंजर्स, गो गेटर्स, वेव राइडर्स, ट्रेल ब्लेजर्स के विद्यार्थियों ने प्रकाश पादुकोण, मैरी कॉम, विश्वनाथ आनन्द, मेजर ध्यानचंद जैसी हस्तियों को जीवंत करते हुए उन्हे खेल उपकरणों के द्वारा तथा उनकी खेल उपलब्धियों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विशेष क्षमता से युक्त छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई सुंदर ड्रिल और रेस ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों ने खेलों के महत्व, अनुशासन, टीम भावना, समर्पण और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया। विभिन्न खेलों से जुड़ी जानकारियों और रचनात्मक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को खेल जगत की गौरवशाली यात्रा से परिचित कराया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि जाग्रत करना तथा उन्हें खेल भावना, परिश्रम और आत्मविश्वास के महत्व से अवगत कराना था। सौ मीटर, रीले रेस ,जैसी विभिन्न खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। मार्चपास्ट,ड्रिल, रेस आदि संपूर्ण अंकों के योग के आधार पर गेम चेंजर्स प्रथम स्थान पर और ट्रेल ब्लेजर्स दूसरे स्थान पर रहा।अंत में विजयी खिलाड़ियों को ट्रॉफी से सम्मानित करते हुए प्रधानाचार्या डॉ. रीना पाठक के द्वारा सभी को ध न्यवाद दिया गया और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई।

विद्यार्थी संविधान की भावना को व्यवहार में उतारें - प्रो. राकेश सिंह

संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन, विद्यार्थियों को दिखाई गई संविधान की मूल प्रति

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपु। उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने भारतीय संविधान की मूल प्रति का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भूमिका के प्रति जागरूक किया। कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि संविध ाान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। विद्यार्थियों को संविधान में प्रदत्त अधि ाकारों के साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे संवैध ाानिक मूल्यों को अपने व्यवहार में अपनाकर ही राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी संविधान की भावना को व्यवहार में उतारकर सशक्त, संवेदनशील और जवाबदेह लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण



भूमिका निभा सकती है। उन्होंने जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में संवैधानिक चेतना विकसित करने के साथ उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। कार्यक्रम में दंतोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल राय और डॉ. राजित राम सोनकर ने विद्यार्थियों को संविधान की मूल प्रति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना, मूल संरचना और स्वतंत्रता के बाद समय–समय पर किए गए संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि संविधान महज कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों का जीवंत आधार है। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए संविधान की समझ विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का पत्रकारिता से गहरा संबंध है।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संविधान दिवस से पूर्व संविधान की मूल प्रति, उसकी प्रस्तावना और संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया से परिचित कराना था। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह, प्रो. मनोज मिश्र, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर, डॉ. इंद्रेश कुमार सहित अन्य शिक्षक और केंद्रीय पुस्तकालय में अध ययनरत विद्यार्थी उपस्थित रहे।

26 को लखनऊ में होगी ताकत की आजमाइश, सपा जारी करेगी घोषणा–पत्र चंद्रशेखर– ओवैसी करेंगे महारैली

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी में चुनावी घमासन शुरू हो चुका है। 26 नवंबर को पड़ने वाले संविधान दिवस के दिन चंद्रशेखर और ओवैसी खनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इस रैली में सात से दस लाख लोगों के आने का अनुमान है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय में पीडीए घोषणा पत्र लॉन्च करेगी। इस कार्यक्रम के बाद संविधान मार्च का आयोजन किया जाएगा। जिसमें



कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर 26 नवंबर 2026 को संविधान दिवस के अवसर पर पार्टी का घोषणापत्र जारी करेंगे, जिसे श्जन–मन का मैनिफेस्टोश नाम दिया गया है और इसके साथ श्सत्ताईस का संकल्परू पीडीए का प्रणपत्रश का नारा जोड़ा गया है। पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन की देखरेख में तैयार किए जा रहे इस घोषणापत्र के जरिए सपा संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण की रक्षा को अपने अभियान के केंद्र में रखते हुए पीडीएमहिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए रोजगार, शिक्षा व सामाजिक न्याय से जुड़े वादे पेश करेगी, जिसके बाद अलग–अलग मंडलों और जिलों के लिए क्षेत्रीय घोषणापत्र भी लाए जाने की योजना हैय चुनाव से काफी पहले इसे जारी करने का मकसद पार्टी को जमीनी स्तर पर जनता के बीच अपने मुद्दों को पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय देना है, जबकि विस्तृत योजनाओं का खुलासा 26 नवंबर के लॉन्च के साथ ही होगा। कांग्रेस की ओर से 26 नवंबर को संविधान दिवस पर प्रदेशभर में संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल होंगे।

प्रधानाचार्या लखबीर चावला ने सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला

आर एल पाण्डेय

लखनऊ। राज कुमार इंटर कॉलेज आलमनगर लखनऊ के प्रांगण में आज भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से वन्दे मातरम् स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें महानगर भाजपा अध यक्ष आनंद द्विवेदी और बहुत से गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।इस अवसर पर आर के शिक्षा के उपाध यक्ष आदरणीय श्री राघव रतन बख्शी जी ने माननीय आनंद द्विवेदी जी को शॉल और स्मृति चिन्ह के रूप में छात्रों द्वारा बनाई हुई कलाकृति भेंट की। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र–छात्राओं ने वन्दे मातरम् गीत प्रस्तुत किया और देशभक्ति से ओत–प्रोत काव्य पाठ किया। आनंद



द्विवेदी ने विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया।विद्यालय परिसर अभिभावकों एवं छात्रों से भरा हुआ था और सभी के लिए जलपान की समुचित व्यवस्था की गई थी।इस कार्यक्रम में रंगमंच से जुड़े हुए अनेक कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दी। गायत्री लोक कल्याण संस्थान राजाजीपुरम के सौजन्य से इस कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्या लखबीर चावला ने उक्त संस्थान द्वारा सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए प्रयासों की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए सांस्कृतिक मूल्यों की महत्व को बताया और उनके उन्नयन का संकल्प लिया।

2027 में भाजपा की जीत होगी, योगी आदित्यनाथ फिर बनेंगे मुख्यमंत्री– मनोज तिवारी

देव दीपावली पर जौनपुर पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी, शीतला चौकिया धाम में जलाए दीप

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दिल्ली से भाजपा सांसद एवं भोजपुरी गायक–अभिनेता मनोज तिवारी देव दीपावली के अवसर पर मंगलवार को देर रात जौनपुर पहुंचे। उन्होंने श्री शीतला चौकिया धाम में मां शीतला के दर्शन–पूजन किए और दीप प्रज्वलित कर सुख–समृद्धि की कामना की। इस दौरान मनोज तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से चौकिया मैया के दरबार में भी देव दीपावली मनाई जा रही है। यहां का तालाब बेहद सुंदर है। उन्होंने बताया कि जौनपुर आने से पहले वह काशी भी गए थे, जहां दशाश्वमेध घाट पर



गंगा आरती में शामिल हुए। वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, जिसके चलते काफी समय लगा।

उन्होंने कहा कि शीतला चौकिया मैया का प्रेम और आशीर्वाद पूरे संसार को मिलता है। वह हर वर्ष यहां आते हैं और आगे भी मां के दरबार में आते रहेंगे।

वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विध ाानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं, आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि परिवार में थोड़ा–बहुत चलता रहता है। बैठकर बातचीत होगी और सब ठीक हो जाएगा।

2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा - केशव मौर्य

टिकट किसी को भी मिले, कार्यकर्ताओं का लक्ष्य कमल खिलानाय एनडीए में मतभेद और गठबंधन में तनाव की चर्चाओं को किया खारिज

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपु। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि भाजपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। टिकट किसी भी नेता या कार्यकर्ता को मिले, पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कमल खिलाने के लिए संकल्पित हैं। भाजपा का लक्ष्य सत्ता में वापसी करना है और संगठन पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी में जुटा है। उक्त बातें उन्होंने बुधवार को जौनपुर पुलिस लाइन स्थित सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहीं। इस दौरान उन्होंने गठबंधन में सीटों के बंटवारे, प्रत्याशियों के चयन, विपक्ष के आरोपों और आगामी विध ाानसभा चुनाव की रणनीति पर अपनी बात रखी।

एनडीए में सब कुछ ठीक, समय पर होगा सीटों का फैसला

सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के संभावित सीट परिवर्तन की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि जिसे जहां से चुनाव लड़ना होगा, वह वहां से लड़ेगा। गठबंधन में सीटों का बंटवारा आपसी बातचीत और बैठकों के बाद तय होगा। संजय निषाद की नाराजगी और एनडीए में कथित तनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा और सहयोगी दलों के बीच कोई विवाद नहीं है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ एकजुट है।

अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना



प्रदेश में श्राधे–राधे कमल खिला देश के उद्घोष पर उन्होंने विश्वास जताया कि न्यायिक प्रक्रिया या आपसी समझौते से भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को शायद आने और जाने के समय के अभिवादन का अंतर समझ में नहीं आता। जाते समय राधे–राधे कहा जाता है।

भाजपा में संगठन तय करता है प्रत्याशी

प्रत्याशियों के चयन पर उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पार्टी नहीं है। यहां जिला, क्षेत्र और प्रदेश स्तर से नामों का पैनल तैयार होकर जाता है। अंतिम निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा घोषणापत्र नहीं, बल्कि संकल्प पत्र जारी करती है, जो पार्टी की प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है।

विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर पलटवार

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से हर घर योजना में घोटाले के आरोपों पर मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वालों को पहले अपने दल का रिकॉर्ड देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने उसके मुख्यमंत्री के जेल जाने का भी जिक्र किया।

60 प्रतिशत वोट भाजपा के साथ होने का दावा

लोकसभा चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि पिछली बार विपक्ष के दुष्प्रचार का असर चुनाव परिणामों पर पड़ा था, लेकिन 2027 का चुनाव डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों के आधार पर होगा। उन्होंने दावा किया कि 60 प्रतिशत वोट भाजपा के साथ हैं और शेष 40 प्रतिशत वोटों में भी पार्टी की हिस्सेदारी रहेगी। पार्टी में भीतरघात और मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि टिकट किसी को भी मिले, सभी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य कमल को जिताना है। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन और न्यायिक रोक वाले मामलों पर टिप्पणी करने से उन्होंने परहेज किया।

बाबा लंगड़ दास की स्मृति में भव्य मेला,तीन किमी मैराथन में शांति और रवि यादव रहे अव्वल

युवाओं को राष्ट्रप्रेम की भावना आत्मसात कर शहीदों को अपना नायक मानना चाहिए – डॉ. सरिता सिंह

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के प्रणेता बाबा लंगड़ दास की स्मृति में हैदरगंज थाना क्षेत्र के जाना बाजार स्थित उनकी समाधि स्थल पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले के अवसर पर तिरंगे के साथ आयोजित तीन किलोमीटर की मैराथन दौड़ में बालिका वर्ग से शांति तथा बालक वर्ग से रवि यादव ने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों, भूतपूर्व सैनिकों, वरिष्ठ नागरिकों और रामलीला समिति के नाट्य कलाकारों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया।कार्यक्रम की शुरुआत बाबा लंगड़ दास की समाधि स्थल से बालक–बालिकाओं की मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ हुई।मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं पूर्व सैनिकों ने संयुक्त रूप से धावकों को रवाना किया। दौड़ समाधि स्थल से शुरू होकर मेला स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई।समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रुप मे आई गौशाईगंज विधायक अभय सिंह की पत्नी डॉ. सरिता सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं के भीतर देश और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत करते हैं।युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और शहीदों के विचारों को आत्मसात करना चाहिए तथा देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को अपना नायक मानकर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैराथन दौड़ के बालिका वर्ग में शांति ने प्रथम, एकता ने द्वितीय तथा काजल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में रवि यादव प्रथम, हिमांशु सिंह द्वितीय तथा संजय दुबे तृतीय स्थान पर रहे। सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंशज महादेव वर्मा, संतोष पांडेय, मोहम्मद मुहीद सलीम सहित दर्जनों पूर्व सैनिकों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। रामलीला समिति जाना बाजार के नाट्य कलाकारों को भी पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता मेला अध्यक्ष चिंतामणि सिंह ने की तथा संचालन मेला संयोजक शेर बहादुर शेर ने किया। समारोह में राममूर्ति तिवारी, प्रबंधक हरिराम भारती, डॉ. मनोज कुमार यादव, सत्यभान सिंह जनवादी सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।इस मौके पर धीरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सैनिक हवलदार भोलानाथ यादव, विनोद कुमार सिंह, रमेश तिवारी उर्फ पप्पू, जेपी सिंह, सत्यभान सिंह जनवादी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीनिवास तिवारी, बृजेश कुमार सहित शिवपाल सिंह, भास्कर तिवारी, रणवीर सिंह, सुभाष तिवारी, विक्रम सिंह, प्रदीप भारती, शनि सिंह, पवन सिंह, शनि शर्मा, सर्वेश सिंह, शिवम शर्मा, आकाश सिंह, कृष्ण सिंह, विवेक, बद्री नारायण सिंह, गया प्रसाद सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।कार्यकर्ताओं ने अतिथियों को फूलमाला पहनाकर एवं अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। मेले में लोक गायक छोटेलाल प्रजापति की टीम ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन किया।मैराथन से लेकर मेला स्थल तक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में हैदरगंज पुलिस के जवानों, जेपी यादव, अमित सिंह, होमगार्ड सीसी राम भारती सहित पुलिसकर्मियों ने सहयोग किया।

यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अयोध्या में बनाये गये 123 परीक्षा केंद्र

इस बार 14 विद्यालयों को बनाया गया नया परीक्षा केन्द्र – डॉ पवन तिवारी



अयोध्या।यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जनपद में कुल 123 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।इस बात की जानकारी देते हुए डीआईओएस डॉ पवन कुमार तिवारी ने बताया कि इस बार इंटर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 14 नए विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है,जबकि पिछले वर्ष परीक्षा केंद्र रहे पांच विद्यालयों को शिकायत मिलने के बाद केंद्र सूची से बाहर कर दिया गया है।बताया कि इस बार भी परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में डीआईओएस कार्यालय ने मानकों के साथ शिकायतों को भी गंभीरता से लिया है।बताया कि इस वर्ष जिले में कुल 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में नौ अधिक हैं।परीक्षार्थियों की सुविधा और परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 14 नए विद्यालयों को परीक्षा केंद्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है।वहीं, पिछले वर्ष केंद्र रहे पांच विद्यालयों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने के बाद उन्हें इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है।बताया कि केंद्र निर्धारण के दौरान विशेष सतर्कता बरती गई है।परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ने से ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों के परीक्षार्थियों को नजदीकी केंद्रों पर परीक्षा देने में सहूलियत होगी।बताया कि यूपी बोर्ड हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

हादसे में घायल डंपर चालक चंद्रिका यादव की उपचार के दौरान मौत

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।पटरंगा थाना क्षेत्र के अशरफपुर गंगरेला गांव निवासी डंपर चालक चंद्रिका यादव की हादसे में घायल होने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। वह स्वतंत्र चेतना अखबार के पत्रकार रमेश यादव के भाई थे।उनके निधन की खबर से परिवार सहित पत्रकार जगत में शोक की लहर है।जानकारी के मुताबिक बुधवार भोर निर्माणाधीन 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मिट्टी ढुलाई के दौरान बिगिनिया पुल के निकट उनका डंपर पलट गया था।हादसे में गंभीर रूप से घायल चंद्रिका यादव को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।चंद्रिका यादव के निधन से तीन बेटियों और एक बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया।परिवार में घटना के बाद से कोहराम मचा हुआ है।उनका अंतिम संस्कार आज सायं चार बजे पैतृक गांव अशरफपुर गंगरेला में किया जाएगा।

श्री गुरूनानक देव जन्मोत्सव सफल बनाने हेतु वारसी कमेटी की बैठक

प्रयागराज, (संवाददाता)। वारसी कमेटी (रजि०) उ०प्र० सरकार प्रयागराज की विशेष बैठक आज कमेटी कार्यालय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद आरिफ वारसी (मुतवल्ली) की अध्यक्षता में की गयी। बैठक में कल मंगलवार को गुरूनानक देव जी महराज के जन्म दिवस पर चर्चा की गयी। अध्यक्ष ने बताया कि उनका जन्म 1469ई0 में तलवंडी गांव में हुआ था जोकि आजकल लाहौर में है। गुरूनानक देव जब 12 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी ने केवल 20 रूपये दिया और यह कहा कि व्यवसाय शुरू करो। तब उन्होंने उस रूपये से गरीबों के लिए खाना खरीदा और सभी में बांट दिया। तत्पश्चात अपने पिता से कहा कि यही सच्चा व्यवसाय है। सन् 1496ई0 में जब वह सन्त बने तभी से वह सभी धर्मों को समभाव से देखा करते थे। वह नीची जातियों से भी कोई भेदभाव नहीं रखा करते थे। गुरु नानक देव जी ने सबके लिये एक समान रसोईघर की व्यवस्था रखी थी जिसमें लंगर किया जाता था और हर धर्म जाति के लोग लंगर खाते थे। मौलाना मोहम्मद आरिफ वारसी ने बताया कि आज भी गुरूद्वारों में सभी जाति–धर्म के लोग इनके मानने वाले अपने घरों में गुरूनानक देव जी के नाम भण्डारा एवं लंगर आयोजित करते हैं। यही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर कमेटी के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण इस्लाम उल्ला वारसी, अरूण कुमार कुशवाहा, इकबाल अहमद वारसी, संगम मिश्रा वारसी, गुलाम निजामउद्दीन वारसी (अयान), खुशहाल सिंह वारसी, मो० नसीम वारसी, राधा कनौजिया वारसी, गौसिया हबीबी, अनीसा बेगम वारसी, अनामिका शर्मा वारसी, इन्तेशा फात्मा वारसी, मो० निजामउद्दीन वारसी (शेरू), शनिपाल वारसी, अफसार अहमद वारसी (पप्पू) आदि शामिल रहे।

मैक्स हॉस्पिटल, लखनऊ ने सुल्तानपुर में कैंसर के इलाज के लिए ओपीडी सेवाएं शुरू की

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

सुल्तानपुर। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ ने सुल्तानपुर के सुमन हॉस्पिटल, गोला घाट, गोमती नगर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की विशेष ओपीडी सेवा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य सुल्तानपुर और आसपास के इलाकों के मरीजों को कैंसर के इलाज से जुड़ी विशेषज्ञ सलाह और सर्जरी की सुविधा के बारे में जानकारी देना है। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर केयर और रोबोटिक सर्जरी के डायरेक्टर – डॉ. कमलेश वर्मा हर महीने के पहले रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सुमन हॉस्पिटल, गोला घाट, गोमती नगर, सुल्तानपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉ. कमलेश वर्मा को कई तरह के कैंसर की सर्जरी और इलाज का अनुभव है। इनमें सिर और गर्दन, ब्रेस्ट, महिलाओं से जुड़े कैंसर, फेफड़े, पेट और आंत, यूरोलॉजिकल और हड्डियों के कैंसर शामिल हैं। उन्हें कैंसर की जटिल सर्जरी, ब्रेस्ट को बचाते हुए कैंसर की सर्जरी, ब्रेस्ट की दोबारा बनावट से जुड़ी सर्जरी, मुंह के कैंसर की सर्जरी के बाद शरीर के दूसरे हिस्सों से टिश्यू लेकर प्रभावित हिस्से को ठीक करने और हड्डियों के कैंसर में हाथ या पैर को बचाते हुए सर्जरी करने का अनुभव है। वे पेट के कुछ गंभीर और बढ़ चुके कैंसर के इलाज के लिए हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी और प्रेशराइज्ड इंट्रापेरिटोनियल एयरोसोल कीमोथेरेपी जैसी आधुनिक तकनीकों से इलाज करने में भी विशेषज्ञता रखते हैं। इन प्रक्रियाओं में पेट के अंदर ही कीमोथेरेपी दी जाती है। इसके अलावा, उन्हें छाती में छोटा चीरा लगाकर की जाने वाली सर्जरी, सिंगल पोर्ट वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक कैंसर सर्जरी का भी अनुभव है। इस पहल पर मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर केयर और रोबोटिक सर्जरी के डायरेक्टर – डॉ. कमलेश वर्मा ने कहा, "कैंसर के इलाज में समय पर जांच, बीमारी की सही पहचान और इलाज की उचित योजना बहुत जरूरी है। सुल्तानपुर में ओपीडी शुरू करने का हमारा उद्देश्य मरीजों को उनके घर के पास ही कैंसर सर्जरी से जुड़े विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध कराना है। यहां मरीज अलग–अलग तरह के कैंसर के बारे में सलाह ले सकते हैं, इलाज के उपलब्ध विकल्पों को समझ सकते हैं और आगे के इलाज के लिए सही मार्गदर्शन पा सकते हैं।" डॉ. वर्मा ने आगे कहा, "हर मरीज के लिए इलाज की योजना उसके कैंसर के प्रकार, स्टेज और सेहत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में नई तकनीकों, जैसे कम चीरे वाली और रोबोटिक सर्जरी, ब्रेस्ट को दोबारा बनाने और शरीर के अंगों को बचाते हुए सर्जरी करने की तकनीकों से कई मरीजों के इलाज के विकल्प बढ़े हैं। समय पर विशेषज्ञ से सलाह लेने से मरीज अपने इलाज के विकल्पों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही फैसला ले सकते हैं।"

इस पहल के जरिए मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ उत्तर प्रदेश में विशेषज्ञ कैंसर सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की अपनी कोशिश को आगे बढ़ा रहा है। सुल्तानपुर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की ओपीडी शुरू होने से मरीजों को समय पर विशेषज्ञ की सलाह, इलाज से जुड़ी जानकारी और आगे की देखभाल में मदद मिलेगी। इससे मरीजों और उनके परिवारों को शुरुआती परामर्श के लिए दूर तक यात्रा करने की जरूरत भी कम होगी।

संविधान दिवस पर बहुजन बाहुल्य बस्तियों में होगा दीपोत्सव कार्यक्रम – डान

प्रयागराज। जनपद के विभिन्न समता न्यायप्रिय अम्बेडकरवादी संगठनो, भारतीय संविधान के पक्षधर विचारकों द्वारा संविधान दिवस की 77 वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर 26 नवम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे से संविधान के सम्मान में संविधान मेला व संविधान महोत्सव 2026 का आयोजन यमुनापार की तहसील बारा के विकास खण्ड शंकरगढ़ के परिसर में एकदिवसीय संविधान पदयात्रा निकालकर संविधान महोत्सव व संविधान मेला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जनपद की समस्त बहुजन बाहुल्य बस्तियों में शाम 07 बजे से संविधान शक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बहुजन बाहुल्य बस्तियों में संविधान के सम्मान में शाम सात बजे दीपक, मोमबत्ती जलाकर इसकी शुरुआत की जाएगी तथा उक्त अवसर पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार भारत के दलित आदिवासी बाहुल्य राज्यो में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग, किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

गोरखपुर, (संवाददाता)। गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल घोषित किए जाने सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर गन्ना समिति के अध्यक्ष अखण्ड प्रताप सिंह, विक्रमजोत चेयरमैन इंजीनियर सिद्धांत सिंह और किसान नेता विनोद सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं और किसानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल किए जाने की मांग उठाई गई। ज्ञापन सौंपने के बाद चेयरमैन इंजीनियर सिद्धांत सिंह और अखण्ड प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि महंगाई के इस दौर में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, सिंचाई, मजदूरी और कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों के दाम बढ़ने से किसानों की लागत काफी बढ़ गई है। ऐसे में 400 रुपये प्रति कुंतल के आसपास गन्ना मूल्य मिलने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार को किसानों की लागत और उनकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अन्य फसलों के मूल्य की घोषणा समय से की जाती है, लेकिन अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया है। इससे किसानों में असमंजस और नाराजगी बढ़ रही है। सरकार को जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित कर किसानों को राहत देनी चाहिए। वहीं किसान नेता विनोद सिंह ने कहा कि जब बाजार में चीनी का मूल्य लगभग 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच रहा है, तो गन्ना किसानों को भी उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार गन्ने का मूल्य 500 से 600 रुपये प्रति कुंतल के बीच निर्धारित करने पर विचार करे, ताकि किसानों की लागत निकलने के साथ उन्हें उचित लाभ भी मिल सके।किसान नेता अरविन्द सिंह ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही किसानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो किसान अपने हक के लिए आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

संक्षिप्त खबरें

डीएम से फसलों की समस्या को लेकर मिले भाकियू पदाधिकारी

बांदा, (संवाददाता)। सिकरी अमान गांव में तालाब के पानी की निकासी न होने से लगभग 45 बीघा किसानों की जमीन जलमग्न हो गई है। खेतों में धान की खड़ी फसल पानी में डूबी हुई है। वहीं आगामी गेहूं एवं चने की बुवाई भी प्रभावित हो रही है। किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों एवं किसानों ने डीएम पुलकित गर्ग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। जिला महामंत्री राजकिशोर सिंह ने बताया कि किसानों ने पहले उपजिलाधिकारी राजापुर को ज्ञापन देकर तालाब के पानी की निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की थी, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। पिछले लगभग दस दिनों से किसान अपनी समस्या को लेकर ब्लॉक एवं तहसील के चक्कर काट रहे हैं। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष राजापुर जसवंत सिंह चौहान, जिला प्रचार मंत्री अजीत कुमार शुक्ला सहित किसान मौजूद रहे। चेताया कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान मजबूर होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

स्वरूप खेल उत्सव में डीएम ने छात्र–छात्राओं का किया उत्साहवर्धन

बांदा, (संवाददाता)। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल में डीएम पुलकित गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर स्वरूप खेल उत्सव सीजन–2 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन एवं व्यायाम सहित विभिन्न खेल गतिविधियों में छात्र–छात्राएं उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम में डीएम ने छात्र–छात्राओं का उत्साहवर्धन किया तथा विद्यालय परिवार द्वारा किए गए स्वागत की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों द्वारा धैर्य, अनुशासन एवं खेल भावना का परिचय देते हुए प्रतिभाग करना सराहनीय है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को पूरे उत्साह एवं ऊर्जा के साथ प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना चाहिए। खेल में जीत और हार से अधिक महत्वपूर्ण सहभागिता, निरंतर अभ्यास एवं खेल भावना होती है। डीएम ने अपने जीवन के खेल संबंधी अनुभव साझा करते हुए बताया कि यदि वे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होते तो उनका उद्देश्य एक खिलाड़ी बनना होता। उन्होंने बताया कि ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी प्राप्त की है ।

मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी लाएं अधिकारी, पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना करें सुनिश्चित–डीएम



सुल्तानपुर, (संवाददाता)। जनपद में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। रविवार को कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभियान के तहत कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

जिलाधिकारी ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने–अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर पात्र नागरिकों को चिह्नित करें और उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना प्रशासन की प्राथमिकता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी जरूरी है। बैठक में डीएम ने महिला मतदाताओं के पंजीकरण में सुधार, जनसंख्या के सापेक्ष मतदाताओं के अनुपात को 64 प्रतिशत से अधिक करने और नए मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को चिह्नित कर उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारियों को मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान रैंप, पेयजल, शेड, शौचालय, बिजली, फर्नीचर, बाउंड्रीवाल, पहुंच मार्ग और दूरभाष नंबरों के प्रदर्शन जैसी सुविधाओं की जांच करने के निर्देश दिए गए। संवेदनशीलता के दृष्टिगत वल्नरेबिलिटी मैपिंग की स्थिति का भी सत्यापन करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी मिले, उनकी सूची तैयार कर संबंधित विभागों के माध्यम से जल्द कमियां दूर कराई जाएं। उन्होंने सभी अधिकारियों से विशेष पुनरीक्षण अभियान की नियमित निगरानी करते हुए अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने को कहा।

विद्यालयों में गूंजी नशा मुक्तिकी आवाज, विद्यार्थियों को दिलाई गई शपथ

सुल्तानपुर, (संवाददाता)। समाज को नशे की बुराई से मुक्त करने और युवाओं को जागरूक बनाने के उद्देश्य से लंभुआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में नशा मुक्ति जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वमान मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गार्गी तिवारी ने छात्र–छात्राओं को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ–साथ पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। युवाओं को अपने बेहतर भविष्य और स्वस्थ जीवन के लिए नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशा न करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की। इस दौरान छात्र–छात्राओं को नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प दिलाते हुए नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में आशीष उपाध्याय, हिमांशु शुक्ला, शिवम शुक्ला समेत विद्यालय के शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं मौजूद रहे।

घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा छोड़ने का आरोप

सुल्तानपुर, (संवाददाता)। अखण्डनगर थाना क्षेत्र के खुशामदपुर गांव में घर में घुसकर एक महिला के साथ कथित रूप से दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर पकड़कर कमरे में बंद किया और डायल–112 पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस ने बिना मुकदमा किए आरोपी को छोड़ दिया। मामले में कार्रवाई न होने से नाराज पीड़िता ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता चंद्रकला पत्नी अनिल कुमार ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 20 नवंबर की रात करीब 12.30 बजे वह घर में सो रही थीं। इसी दौरान गांव का ही राजेश कुमार पुत्र अच्छेलाल घर का चौनल खोलकर अंदर घुस आया। आरोप है कि उसने महिला के मुंह पर गमछा डालकर उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर बरामदे में सो रहे ।

अयोध्या मंडल में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व,इंटर प्रायोगिक परीक्षाएं 11 से 19 जनवरी तक

अयोध्या।यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित होंगी। अयोध्या मंडल को प्रथम चरण में रखा गया है।यहां 11 जनवरी से 19 जनवरी 2027 तक प्रायोगिक परीक्षाएं कराई जाएंगी।प्रथम चरण में अयोध्या समेत नौ मंडल शामिल हैं। परीक्षाओं की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से होगी तथा रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी।यह जानकारी डीआईओएस डॉ पवन कुमार तिवारी ने दिया।

पीएम सूर्यघर योजना के लंबित आवेदनों पर डीएम सख्त, सात दिन में निस्तारण के निर्देश

सुल्तानपुर, (संवाददाता)। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी को लेकर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों और सोलर वेण्डरों को निर्देश दिया है कि योजना के तहत लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। खासकर बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या सात दिनों के भीतर कम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी कि अनावश्यक देरी या लापरवाही सामने आने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक हुई। इसमें मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीएम ने सोलर वेण्डरों से बातचीत कर बैंक और विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली तथा उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। समीक्षा में सामने आया कि बैंक स्तर पर कुल 722 आवेदन लंबित हैं। इस पर सीडीओ ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे अपना मोबाइल नंबर संबंधित वेण्डरों को उपलब्ध कराएं,।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।